

झांसी जिले में तांबे के निषेप

4306. दा० पोविल दास रिक्षारिया : क्या इस्पात और खान मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) सरकार ने झांसी जिले में मदावरा में तांबे के निषेपों के पता लगाने और वहां खुदाई कार्य आरम्भ करने के लिए कोई अध्ययन दल भेजा है ; और

(ख) यदि हाँ, तो इस बारे में अब तक क्या प्रगति हुई है और नियमित आधार पर कब से तांबा निकालना आरम्भ हो जायेगा ?

इस्पात और खान मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री शाह नवाज खां) : (क) भारतीय भूवैज्ञानिक सर्वेक्षण ने झांसी जिले के माडावारा में तांबे निषेपों की सम्भावना वो समन्वेषित करने के लिए प्रारम्भिक सर्वेक्षण आरम्भ किया है। अभी तक भूस्थायन अन्वेषणों के लिए उथले एक मीटर के छिद्रों को छोड़कर कोई खुदाई कार्य नहीं किया जा रहा है।

(ख) 1900 भूस्थायन नमूनों को एकत्रित किया गया है और अग्रिम कार्य के लिए अध्ययनाधीन है। अभी तक किसी भी प्रकार की तांबे विषमतायें ध्यान में नहीं आई हैं लेकिन कतिपय निकल विषमताओं का भमागत हुआ है।

चूंकि अन्वेषण अभी प्रारम्भिक अवस्था में है, अतः अभी वह नहीं कहा जा सकता है कि धातु का निष्कर्षण साध्य होगा अथवा नहीं और यदि साध्य भी हुआ तो यह नहीं कहा जा सकता है कि वह कब तक होगा।

Study of Cost of Production of Sugarcane by Rajendra Agriculture University, Bihar

4307. SHRI N. K. SINHA : Will the Minister of AGRICULTURE be pleased to state whether Government propose to entrust Rajendra Agriculture University, Bihar to assess the cost of production of sugarcane per acre in Bihar as entrusted to other Universities in the country ?

THE MINISTER OF STATE IN THE MINISTRY OF AGRICULTURE (SHRI SHER SINGH) : The Central Government have initiated a comprehensive scheme for studying the cost of cultivation of principal crops in different States in the country. The implementation of this scheme in Bihar has been entrusted to the Rajendra Agricultural University. Under this scheme, studies on the cost of production of different principal crops, including sugarcane, would be taken up in a phased manner.

नहरों तथा नदियों द्वारा न सीचे जाने वाले क्षेत्रों में सिचाई हेतु कुएं खोदने के लिए सर्वेक्षण करना

4308. श्री जगन्नाथ मिश्च : क्या कृषि मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) नहरों अथवा नदियों अथवा उप-नदियों द्वारा न सीचे जाने वाले क्षेत्रों में पांच एकड़ भूमि के लिए 1 कुओं के हिसाब से भूमि की सिचाई के लिए कुल कितने कुओं की आवश्यकता होगी ;

(ख) क्या सरकार प्रत्येक खेत के लिए गिर्चाई सम्बन्धी सुविधाओं की व्यवस्था करने हेतु अगले वर्ष तक अपेक्षित कुओं की खुदाई कराने की आवश्यकता में नहीं है ;

(ग) क्या ऐसा सर्वेक्षण अब तक नहीं किया गया है ; और

(घ) यदि हाँ, तो क्या हाल ही में किये गये जनरलना कार्य की रिपोर्ट के आधार पर कार्यवाही नहीं की जा सकती है ?

कृषि मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री शेर सिंह) : (क) यदि प्रत्येक पांच एकड़ भूमि के लिए एक कुओं बनाना काफी है तो अब तक सिचाई की सुविधाओं से वंचित क्षेत्रों को सीचने के लिए लगभग 6 करोड़ कुओं की आवश्यकता होगी। वास्तव में देश में उपलब्ध भूमिगत जल के अनुमानित साधन देश के सिचाई की सुविधाओं से रहित कुल क्षेत्र के केवल कुछ अंश (लगभग